भारत सरकार
सहकारिता मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न 353
मंगलवार, 02 दिसंबर, 2025/11 अग्रहायण,1947 (शक) को उत्तरार्थ

प्राथमिक कृषि सहकारी ऋण समितियां

+353. श्री अनुराग शर्माः

क्या **सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में कार्यशील प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पीएसीएस) की वर्तमान स्थिति क्या है और उनकी डेयरी तथा मत्स्य सहकारी समितियों को बढ़ावा देने में भूमिका क्या है;
(ख) सरकार द्वारा आधुनिकीकरण, कम्प्यूटरीकरण और डेयरी, मत्स्यपालन और अन्य आय-उत्पादक उद्यमों जैसी संबद्ध कार्यकलापों में विविधीकरण के माध्यम से पीएसीएस को मजबूत करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;
(ग) क्या किसानों की आय और ग्रामीण रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए झांसी में पीएसीएस या सहकारी समितियों हेतु कोई विशिष्ट योजना चलाई गई है या वित्तीय सहायता प्रदान की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(घ) इन पहलों के परिणामस्वरूप किसानों और इन समितियों के सदस्यों को प्राप्त हुए लाभों का ब्यौरा क्या है, जिसमें लाभार्थियों की संख्या, उत्पादन में वृद्धि और ऋण सुविधा में सुधार या आजीविका के परिणाम शामिल हैं?

उत्तर

सहकारिता मंत्री
(श्री अमित शाह)

(क) और (ख): राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस (NCD) के अनुसार, उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में 67 प्राथमिक कृषि क्रेडिट समितियां (PACS) काम कर रही हैं। PACS डेयरी और मात्स्यिकी विकास सहित ग्रामीण आर्थिक कार्यकलापों की श्रृंखला का समर्थन कर रही हैं। आधुनिकीकरण, कंप्यूटरीकरण और कार्यशील विविधीकरण पर ध्यान केंद्रित करते हुए PACS को सशक्त करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सुधारों की एक श्रृंखला शुरू की गई है । केंद्रीय प्रायोजित PACS कंप्यूटरीकरण परियोजना, 2,925.39 करोड़ रुपये के बढ़े हुए वित्तीय परिव्यय के साथ, पारदर्शी लेखांकन, बेहतर सेवा वितरण और DCCBs, StCBs और नाबार्ड के साथ निर्बाध कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए 79,000 से अधिक PACS को ईआरपी-आधारित कॉमन राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर पर ला रही है। आदर्श उप-विधियाँ PACS को 25 से अधिक बहुउद्देशीय व्यावसायिक कार्यकलापों जैसे डेयरी संग्रह केंद्र, मात्स्यिकी सहायता सेवाएं, भंडारण, उर्वरक और बीज वितरण, CSC प्रचालन, PMKSK कार्य, LPG वितरक और प्रापण आदि कार्यों को करने में सक्षम बनाते हैं। पंचायत स्तर पर नई बहुउद्देशीय, डेयरी और मात्स्यिकी सहकारी समितियों की स्थापनाओं की व्यापक पहल झांसी में PACS के लिए संगठित दुग्ध प्रापण, मूल्य-वर्धित सेवाओं और मात्स्यिकी पालन आधारित आजीविका के लिए समर्थन को बढ़ावा देने में भाग लेने के अवसरों को और सशक्त करती है। PACS कंप्यूटरीकरण परियोजना के तहत झांसी में 62 PACS अनुमोदित हैं, जिनमें से 48 को ईआरपी प्लेटफॉर्म पर ऑनबोर्ड किया गया है और सभी 48 ने गो-लाइव स्तर भी प्राप्त कर लिया है।

(ग) और (घ): झांसी में PACS और सहकारी समितियां पूरे उत्तर प्रदेश में लागू केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं और वित्तीय सहायता तंत्र के तहत आती हैं। PACS कंप्यूटरीकरण परियोजना के तहत, उत्तर प्रदेश को वित्त वर्ष 2022-23, 2023-24, 2024-25 और 2025-26 में वित्तीय सहायता के रूप में 67.10 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं, जिसका एक हिस्सा झांसी जिले में संचालित PACS को सीधे लाभ पहुंचाता है । ये फंड हार्डवेयर प्रापण, ईआरपी परिनियोजन, प्रशिक्षण और सामाजिक स्तर पर सहायता प्रणालियों की स्थापना का समर्थन करते हैं।

झांसी जिले में PACS को सशक्त करने, किसानों की आय बढ़ाने और ग्रामीण रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए कई योजनाएं और वित्तीय इंटरवेंशन कार्यान्वित किए जा रहे हैं। इंडियन सीड कोऑपरेटिव लिमिटेड में कुल 55 समितियों ने सदस्यता ली है, और 04 PACS ने बीज उत्पादन इकाइयों की स्थापना के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और रोजगार पैदा होंगे ।

पांच समितियों ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) में सदस्यता ले ली है, और चार समितियां राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड (NCOL) में शामिल हो गई हैं, जिससे जैविक कृषि कार्यकलापों के लिए अवसर पैदा हुए हैं और वित्तीय संधारणीयता में सुधार हुआ है। वर्ष 2023 और 2025 में आयोजित सदस्यता अभियान ने उन किसानों को सदस्य के रूप में शामिल होने में सक्षम बनाया जो पहले PACS से जुड़े नहीं थे; परिणामस्वरूप, 1,74,427 किसान PACS के सदस्य बन गए हैं और उन्हें 13,830.06 लाख रुपये का ऋण प्राप्त हुआ है। इसके अतिरिक्त, जिले के सभी PACS, CSC सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, जिससे संस्थागत आय बढ़ रही है और ऑनलाइन सेवाओं तक किसानों की पहुंच में सुधार हो रहा है।

झांसी के आठ PACS ने PM पशु चिकित्सा केंद्र स्थापित करने के लिए आवेदन किया है, जो आवश्यक पशुधन स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करेंगे और साथ ही रोजगार पैदा करते हुए समितियों की वित्तीय स्थिति में सुधार करेंगे । सदस्यों को PACS के माध्यम से नियमित रूप से यूरिया, DAP और NPK सहित उच्च गुणवत्ता वाले बीज और उर्वरक भी प्रदान किए जाते हैं, जो कृषि उत्पादन में वृद्धि में योगदान करते हैं। इसके अलावा, PACS समय पर किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) ऋण की सुविधा प्रदान करते हैं, जिससे किसानों को फसल की खेती, पशुधन प्रबंधन और अन्य कृषि आवश्यकताओं के लिए किफायती ऋण प्राप्त करने में मदद मिलती है।

जिले में तेरह PACS ने तेरह किसान उत्पादक संगठनों (FPOs) के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं जिससे सहकारी संबंध मजबूत हुए हैं और वित्तीय परिणामों में सुधार हुआ है।

झांसी जिले में चल रही पहलों के अंतर्गत किसानों और PACS के सदस्यों को महत्वपूर्ण लाभ मिल रहा है। वर्ष 2024-25 में, कुल 18,226 किसानों को ₹13,819.57 लाख का फसल ऋण प्राप्त हुआ, जिससे उन्हें फसल क्षमता और समग्र उत्पादन में सुधार करने में मदद मिली। इसी तरह, अप्रैल से अक्टूबर 2025 तक, 13,628 किसानों को 12,482.94 लाख रुपये का ऋण प्राप्त हुआ, जिससे कृषि में निवेश करने की उनकी वित्तीय क्षमता और मजबूत हुई। PMKSK योजना और उर्वरक सब्सिडी कार्यक्रमों के तहत, उर्वरकों की समय पर आपूर्ति से कृषि उत्पादकता में वृद्धि हुई है: 2024-25 में, 94,520 किसानों को 17,016.40 मीट्रिक टन यूरिया प्राप्त हुआ और 91,850 किसानों को 16,074.10 मीट्रिक टने DAP प्राप्त हुआ; 2025-26 में, 79,545 किसानों को 12,530 मीट्रिक टन यूरिया, 1,25,387 किसानों को 20,062 मीट्रिक टन DAP प्राप्त हुआ, और 1,840 मीट्रिक टन NPK भी वितरित किया गया। समय पर इन आपूर्ति ने सीधे तौर पर किसानों के लिए उच्च पैदावार और अधिक आय में योगदान दिया है। जिला सहकारी बैंक में 2,23,212 किसानों के बैंक खाते हैं और वे विभिन्न बैंकिंग सेवाओं से लाभान्वित हुए हैं, जिससे उनकी ऋण पहुंच, बचत व्यवहार और समग्र आजीविका परिणामों में सुधार हुआ है।

*****